बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 166

कम हो आरबीआई पर निर्भरता

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है। यह रिपोर्ट बीते वर्ष के दौरान उसके कदमों को स्पष्ट तो करती ही है, वह व्यापक अर्थव्यवस्था की आगे की दिशा के अनुमानों को भी रेखांकित करती है। यह सालाना रिपोर्ट उस वक्त आई है जब चंद रोज पहले ही यह खबर सामने आई कि आरबीआई 1.7 लाख करोड़ रुपये की राशि सरकार को हस्तांतरित करेगा। इसमें से 1.23 लाख करोड़ रुपये की राशि अधिशेष से आई है जबकि शेष राशि अतिरिक्त प्रावधान से प्राप्त की गई है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान के नेतृत्व वाली एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। अधिशेष की राशि की अधिकता के लिए आरबीआई द्वारा खुले बाजार में परिचालन में इजाफा भी एक वजह है। यह तेजी वर्ष की दूसरी छमाही में खास तौर पर देखी गई। इस अवधि में खुले बाजार में परिचालन से 2.5 लाख करोड़ रुपये की राशि हासिल हुई। बहरहाल, वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नकदी की कमी बनी हुई है और 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य की भारी भरकम नकदी बाजार में डाले जाने के बावजूद इसकी कमी बरकरार है। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि बैंकिंग तंत्र में नकदी की स्थिति सहज है। हालांकि इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वित्त वर्ष 2019 में नकदी समायोजन व्यवस्था के तहत नकदी डालने का सिलसिला जारी रहा और ऋण की स्थिति कमजोर बनी रही।

व्यवस्था में नकदी को लेकर भविष्य का परिदृश्य अहम है। देखना होगा कि आरबीआई से नकदी का हस्तांतरण एक बार के लिए हुआ है या ऐसा बार-बार होता रहेगा। आरबीआई को इतने बड़े पैमाने पर नकदी का हस्तांतरण क्यों करना पड़ा, इसे लेकर रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है। ऐसा मोटे तौर पर विदेशी मुद्रा से जुड़ी गतिविधियों और व्यापक मुद्रा विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया।

आरबीआई को यह भी लगता है कि व्यवस्था में नकदी डालने का प्रभाव 2018-19 में निपट चुका है जब मुद्रा और जीडीपी अनुपात 10.7 से 11.2 हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष के दौरान तंत्र में नकदी की स्थिति अधिशेष से घाटे की हो गई। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने पूंजी के बहिर्गमन और प्रचलित मुद्रा में विस्तार को भी नकदी की स्थिति के लिए वजह बताया। जाहिर है सरकार आरबीआई से इतने अधिक हस्तांतरण पर स्थायी रूप से निर्भर नहीं रह सकती है और उसे अपनी निर्भरता कम करनी होगी।

यह बात ध्यान देने लायक है कि आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट से यह संकेत दिया है कि बाहरी संकट से बचाव के लिए सतर्कता की आवश्यकता है और वह लगातार इस पर निगाह रख रहा है। यह वर्ष 2013 में अमेरिकी बाजारों में हुई प्रतिक्रिया से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि तब से अब तक पोर्टफोलियो प्रवाह की संवेदनशीलता में काफी इजाफा हुआ है।

वार्षिक रिपोर्ट को भले ही आश्चर्यजनक रूप से आशावादी माना जा रहा हो, मिसाल के तौर पर सरकारी घाटे की वृद्धि के विषय पर, लेकिन एक ओर जहां यह घरेलू वृद्धि को रेखांकित करती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के नुकसान से जुड़े जोखिमों की भी बात करती है। वहीं दूसरी ओर इसमें यह भी कहा गया है कि भारत ढांचागत समस्याओं के बजाय चक्रीय मंदी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसमें श्रम, कृषि विपणन, भूमि जैसे ढांचागत मुद्दों का भी उल्लेख है जिन्हें हल करने की आवश्यकता है।

आरबीआई ने दोहराया है कि वह खपत की मांग बढ़ाने को प्रतिबद्ध है और निजी निवेश चालू वर्ष में उसकी शीर्ष प्राथमिकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चूंकि मुद्रास्फीति निकट भविष्य में नियंत्रण में रहेगी इसलिए आरबीआई भविष्य में नीतिगत दरों में और कटौती करने की स्थिति में रहेगा।

अजय मोहंती

दूरसंचार विभाग के जागने का वक्त

छोटी कंपनियों का कारोबार से बाहर होना, आरकॉम का दिवालिया होना, बढ़ता कर्ज तथा बैंक परिसंपत्तियों पर दबाव जैसे लक्षण बता रहे हैं कि अब चेतने का वक्त आ चुका है। विस्तार से बता रहे हैं राहुल खुल्लर

दूरसंचार क्षेत्र पिछले काफी समय से संकट से दोचार है। इससे जुड़ी चेतावनी स्पष्ट रूप से हमारे सामने रही है। छोटी कंपनियों का कारोबार से बाहर होना, आरकॉम का दिवालिया होना, बाजार में पहले से काम कर रही कंपनियों को भारी नुकसान और बढ़ता कर्ज तथा बैंक परिसंपत्तियों पर तनाव देखने को मिलता रहा है। इन बातों के बीच सरकार की निष्क्रियता और लापरवाही तमाम दलीलों से परे है।

औद्योगिक स्तर का तर्क अपनाएं तो राजस्व में सालाना 5 से 9 फीसदी की दर से वृद्धि होती रही है। बीते चार वर्ष में उद्योग जगत का राजस्व 20 फीसदी गिरा। दूरसंचार कंपनियों की बात करें तो टावर कारोबार को छोड़कर उनका बाकी कर्ज तीन गुना हो चुका है और अब इसकी राशि 4.3 लाख करोड़ रुपये हो चुकी है। अब यह कर्ज सालाना राजस्व का 2.6 गुना हो चुका है। सरकार का राजस्व (लाइसेंस और स्पेक्ट्रम शुल्क) 36 फीसदी गिरा है।

इससे इतर अगर निजी क्षेत्र पर नजर डालें तो टाटा टेली सर्विसेज, आरकॉम, एयरसेल, टेलीनॉर और वीडियोकॉन कारोबार से बाहर हो चुकी हैं। चार वर्ष में कर्ज करीब चार गुना हो चुका है और इसमें 2.8 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। आइडिया-वोडाफोन और जियो, प्रत्येक पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। वर्ष 2018-19 में कर्ज, सालाना राजस्व का तीन गुना था। दो बड़ी कंपनियों ने बीते तीन वर्ष में घाटा होने की बात कही है। वर्ष 2015-16 में जब कर्ज का स्तर अपेक्षाकृत कम था, तीन बड़ी कंपनियों का कर एवं ब्याज पूर्व मार्जिन 34 फीसदी था। वर्ष 2018-19 में यह मार्जिन घटकर 25 फीसदी रह गया। एक कंपनी के लिए तो यह मात्र 13 फीसदी रहा।

सरकारी क्षेत्र की तस्वीर और निराश करने वाली है। बीते चार वर्ष में बीएसएनएल का राजस्व 40 फीसदी और एमटीएनएल का राजस्व 30 फीसदी गिरा। बीएसएनएल और एमटीएनएल 2013-14 से लगातार परिचालन घाटा दर्शा रही हैं। 2018-19 में बीएसएनएल का घाटा 14,000 करोड़ रुपये से अधिक था। समेकित घाटा 90,000 करोड़ रुपये था। एमटीएनएल का घाटा उसके राजस्व से अधिक है और उसका कर्ज राजस्व का नौ गुना हो चुका है। सरकार इस दिशा में कुछ खास नहीं कर सकी है।

बाजार में ढेर सारी कंपनियां थीं और ऐसे में एक झटका जरूरी था। निकासी और दिवालिया ही विकल्प रह गए थे। इतना ही नहीं जियो का प्रवेश उठापटक वाला होना ही था। सफलता का इकलौता रास्ता यही था। शून्य कीमत पर सेवा देना इसकी मांग की सबसे बड़ी वजह बना। इसके कारण कीमतों की जो जंग छिड़ी उसने कंपनियों की वित्तीय हालत खराब कर दी।

परंतु यहां सबके लिए समान अवसर नहीं थे। नियामकीय कदम आर्थिक तकदीर तय करने का नया माध्यम बन गए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आंखें मूंदे रखीं और निःशुल्क सेवा जारी रहने दी। समापन शुल्क संबंधी उसके आदेश ने जियो की लागत कम की और उसके प्रतिद्वंद्वियों का राजस्व कम किया। इसके बाद आक्रामक कीमतों से संबंधित ट्राई का अत्यंत बुरा आदेश आया। जियो लागत से कम मूल्य पर सेवा देने में सक्षम था क्योंकि वह दूसरों पर हमला करने वाला नहीं था। अन्य कंपनियां परभक्षी की ऐसी श्रेणी में थीं क्योंकि उनके पास पहले से बाजार हिस्सेदारी थी। इस आदेश में अन्य प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रावधान थे। दूरसंचार विवाद निस्तारण एवं अपील पंचाट ने 18 महीने बाद आदेश के प्रावधानों को खारिज कर दिया लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। दूरसंचार विभाग के जिस सचिव ने सरकार और उद्योग जगत के गिरते राजस्व की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था, उनका जल्द ही तबादला कर दिया गया।

इस गहन वित्तीय तनाव ने सरकारी बैंकों के लिए फंसे हुए कर्ज की छाया का विस्तार किया। इससे भी अहम बात यह है कि इसने दीर्घावधि की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर सवाल खड़े कर दिए। गणित लगाकर देखिए। अगर कर्ज और राजस्व का अनुपात 2.5 है तो ऋण की लागत को 8 फीसदी मानें तो केवल कर्ज की भरपाई के लिए ही 20 फीसदी राजस्व की आवश्यकता होगी। इसके स्पेक्ट्रम की लागत के क्षरण और अवमूल्यन को इसमें और जोड़ दीजिए। जिन दो कंपनियों के आंकड़े उपलब्ध हैं उनका अवमूल्यन और क्षरण क्रमशः राजस्व का 20 फीसदी और 11 फीसदी है।

यह उद्योग पूंजी आधारित है लेकिन इसकी विशिष्टता है तकनीक का तेजी से पिडड़ना। 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी 2010 में हुई थी। सन 2012 में 3जी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल शुरू हुआ। 2019 में उसके बंद होने की खबर आ रही है। इससे पूंजी, उपकरण और नेटवर्क तीनों की क्षति होती है। जाहिर है 5जी को लेकर इस आपाधापी में थोड़ा ठहरकर हमें सोचना चाहिए कि आखिर 4जी में लगी कितनी पूंजी का इससे नुकसान होने वाला है? 4.3 लाख करोड़ रुपये के बकाया कर्ज का क्या होगा? अगर नीलामी होती है तो क्या घरेलू बैंकिंग उद्योग जरूरत पूरी कर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल भारी पूंजी वालों को लाभ होगा और यह उद्योग एकाधिकार की ओर बढ़ने लगे।

स्पेक्ट्रम की अनापशनाप कीमतें कर्ज में इजाफे की प्रमुख वजह हैं। स्पेक्ट्रम की कम उपलब्धता के कारण कीमतें बहुत बढ़ गईं। देश में प्रति मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के 86 लाख उपभोक्ता हैं। जर्मनी में 1.70 लाख, जापान में 2.62 लाख, कोरिया में 1.37 लाख और अमेरिका में ये 5.89 लाख हैं। देश में प्रति ऑपरेटर औसत धारिता 31 है जबकि यूरोप में यह 61 और एशिया में 49 है। सरकार को स्पेक्ट्रम जारी करने के पहले उचित अध्ययन कर लेना चाहिए, इसके बाद ही उसे स्पेक्ट्रम जारी करना चाहिए। ऐसा न करने से ऊंची कीमतों की समस्या बनी रहेगी।

न्यूनतम शुल्क में सुविधा देने की होड़ समाप्त होनी चाहिए। यहां तक कि मुनाफा कमा रही एकमात्र कंपनी जियो भी पैसे नहीं कमा रही। अगर कंपनियों के पास आंतरिक संसाधन नहीं हों तो भविष्य का निवेश प्रभावित होता है।

शंपटर के रचनात्मक विध्वंस के सिद्धांत में नवाचार और प्रतिस्पर्धी बाजारों का जिक्र था। प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष नहीं रही है। नियामकीय प्रभुत्व के बारे में खुलकर चर्चा की गई है। दूरसंचार एक ध्वंसात्मक रचना रही। जरूरत इस बात की है कि नियामकीय निर्णयों में संतुलन और निष्पक्षता लाई जाए। फिर चाहे वह नियामक ट्राई हो या दूरसंचार विभाग। उद्योग जगत के नियमन का उद्देश्य था सेवा प्रदाताओं के हितों का बचाव करना और दूरसंचार क्षेत्र की व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करना। दुख की बात है कि इसे भुला दिया गया है। अब वक्त आ गया है कि दूरसंचार विभाग जाग जाए।

(लेखक ट्राई के पूर्व चेयरमैन हैं)

नाभिकीय ऊर्जा से चालित मिसाइल से गंभीर खतरा

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

रूस के नाइनोक्सा मिसाइल परीक्षण रेंज में 8 अगस्त को हुई दुर्घटना ने आधुनिक हथियारों के विकास से जुड़े भयावह पहलुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। रूसी परमाणु ऊर्जा आयोग 'रोसेटम' का कहना है कि नाभिकीय ऊर्जा-चालित तरल ईंधन वाले जेट प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। इस हादसे में पांच तकनीकी कर्मचारियों की मौत हो गई और स्थानीय इलाके में रेडियोधर्मिता का स्तर 16 गुना तक बढ़ जाने के बाद स्थानीय निवासियों को सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा। वैसे चेर्नोबिल हादसे की तुलना में यह दुर्घटना उतनी खतरनाक नहीं है। चेर्नोबिल हादसे के बाद रेडियोधर्मिता सामान्य स्तर से 7,000 गुना हो गई थी।

नाभिकीय ऊर्जा-चालित उड़ान के बारे में शोध 1950 के दशक में शुरू हो गया था। शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ दोनों को लगता था कि हथियारों के विकास में नाभिकीय ऊर्जा पर निर्भर उड़ान अहम हो सकती है। लेकिन 1960 का दशक शुरू होने तक दोनों देशों ने ही इस शोध को रोक दिया। दरअसल परमाणु ऊर्जा पर आश्रित मिसाइल के विकास में जुड़ी इंजीनियरिंग समस्याएं काफी गंभीर किस्म की थीं।

चेर्नोबिल, थ्री माइल आइलैंड, फुकूशिमा के परमाणु संयंत्रों में हुए हादसों और कुर्स्क परमाणु पनडुब्बी के डूबने से रिएक्टरों के शुरुआती डिजाइनों की खामी सामने आ चुकी थी। इसके बावजूद नाभिकीय ऊर्जा वाले जहाजों एवं बिजली संयंत्रों के लिए रिएक्टर डिजाइन करना अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन उड़ान से संबंधित प्रोपल्शन सिस्टम को ताकत एवं वजन के बीच बढ़िया अनुपात चाहिए होता है ताकि उसे अधिक ताकत मिले और वजन कम रहे।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के साथ समस्या यह है कि वे वजन में भारी होते हैं। इंसानों को ले जाते समय जानलेवा विकिरण से बचाव के लिए सघन सुरक्षा कवच की जरूरत होती है। इसके अलावा उष्मा के ऊंचे स्तर पर काबू पाने की भी समस्या होती है। साठ के दशक तक अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों ने ही ऐसे जेट इंजन बनाने की इंजीनियरिंग क्षमता हासिल कर ली थी जिनकी ताकत एवं वजन अनुपात परमाणु संयंत्रों से अधिक था। परंपरागत रॉकेट भी भार के अनुपात में अधिक ताकत निकाल लेते हैं।

मार्च 2018 में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने कई नए हथियारों के विकास की घोषणा की थी। फरवरी 2019 में बुरेवेस्तनिक मिसाइल के मद्देनजर विकसित छोटे परमाणु संयंत्र का परीक्षण सफल रहने की घोषणा की गई। क्रूज मिसाइलें धरती की सतह के बेहद करीब से उड़ान भरती हैं जिससे वे रडार की पकड़ में भी आने से बच जाती हैं। कम रफ्तार से उड़ान भरने से इन्हें अधिक ताकत की जरूरत नहीं होती है, लिहाजा नाभिकीय इंजन काफी छोटा भी हो सकता है।

एक नाभिकीय संयंत्र का फायदा यह है कि बहुत लंबे वक्त तक दोबारा ईंधन डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमाणु ऊर्जा से लैस मिसाइल में अगर कुछ किलोग्राम नाभिकीय ईंधन भी हो तो वह वर्षों तक तैनात रह सकती है जिससे उसकी मारक क्षमता असीमित हो जाती है। मिसाइल में एक स्मार्ट कंप्यूटर लगाकर उसका उड़ान पथ बदलने की प्रोग्रामिंग की जा सकती है जिससे उसे पकड़ पाना और मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि इस उड़ान प्रणाली का असली डिजाइन गोपनीय है। लेकिन पुराने प्रयोगों से यही लगता है कि किसी भी इंजन को परंपरागत तरीके से शुरू करने के बाद नाभिकीय ईंधन पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मिसाइल इस नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल कई तरह से कर सकती है। रेडियोधर्मी ह्रास से पैदा होने वाली ऊष्मा को सीधे बिजली में तब्दील किया जा सकता है। नासा ने अपने क्यूरिऑसिटी रोवर में यही तरीका अपनाया है। दूसरा तरीका रेडियोधर्मी ताप का इस्तेमाल परंपरागत तरल ईंधन वाले रॉकेट को प्रज्वलित करने का है।

हालांकि सबसे अधिक मुमकिन डिजाइन काफी हद तक परमाणु चालित रैमजेट जैसा होगा। एक रैमजेट टर्बोचार्जर की तरह होता है जो तेज रफ्तार पर चल रहे वाहन में ही काम कर सकता है। तेज गति से चलने के दौरान ही इंजन के चैंबर में हवा जमा होती है और फिर वह गर्म हो जाती है। इस गर्म हवा को बाहर निकाल दिया जाता है जिससे एक धक्का पैदा होता है। लेकिन हवा को गर्म करने के लिए रेडियोधर्मी ऊष्मा का इस्तेमाल करें तो एक नाभिकीय रैमजेट सिद्धांत रूप में वर्षों तक उड़ता रह सकता है। सिद्धांत रूप में इसके मैक-10 की अविश्वसनीय रफ्तार हासिल कर लेने की भी संभावना है।

इससे जुड़ी इंजीनियरिंग समस्याएं भी हैं। नाभिकीय प्रक्रिया के दौरान पैदा होने वाली ऊष्मा बहुत अधिक होती है और उतने ऊंचे तापमान पर टिक पाने वाली हल्के वजन की सामग्री लगा पाना मुश्किल है। वजन संबंधी सीमाओं के चलते रेडियोधर्मी आवरण भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उड़ान पथ के दौरान बाहर निकलने वाली उष्मा भी रेडियोधर्मिता फैलाती जाएगी। इसका मतलब है कि एक बार छोड़ दिए जाने के बाद परमाणु ऊर्जा-चालित मिसाइल में परमाणु बम नहीं लगा होने पर भी कुछ मात्रा में रेडियोधर्मी अवशेष निकलता रहेगा।

इस दिशा में शोध कार्य रोके जाने के पीछे यही कारण रहे हैं। शीतयुद्ध के झंडाबरदारों ने भी रेडियोधर्मी अवशिष्ट निकालने वाली मिसाइलों के विचार को त्याग दिया था। लेकिन इस दिशा में शोध कार्य एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। पुतिन ने साफ कहा है कि रूस को मिसाइल-रोधी आवरण से बच सकने वाले हथियारों की जरूरत है। नई सामग्री एवं कृत्रिम मेधा से इस दिशा में कुछ इंजीनियरिंग सीमाओं को तो दूर किया जा सकता है लेकिन उनसे भी रेडियोधर्मी अवशिष्ट का खतरा कम नहीं हो सकता है। इक्कीसवीं सदी में मिसाइल डिजाइन का नया दौर शीतयुद्ध की तुलना में कहीं अधिक डरावने हालात पैदा कर सकता है।

कानाफूसी

फिसल गई जुबान

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर पिछले दिनों एक संवाददाता सम्मेलन में शब्दों की कमी से जूझते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी कश्मीर से संबंधित टिप्पणियों ने देश का अपमान किया है और पाकिस्तान को मौका दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र में भारत को निशाना बना सके। राहुल ने ट्वीट करके कहा था कि कश्मीर में हिंसा के कारण लोगों की जान जा रही है। पाकिस्तान ने इस ट्वीट को संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ अपनी याचिका में शामिल किया। जावड़ेकर ने मांग की कि राहुल गांधी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए क्षमा मांगें। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल ने बाद में लोगों की नाराजगी देखकर पाकिस्तान पर हमला करते हुए और कश्मीर को भारत का आंतरिक मसला बताते हुए ट्वीट किए। जावड़ेकर ने यह भी कहा कि संसदीय क्षेत्र बदल जाने के कारण राहुल की मानसिकता में भी बदलाव आ गया है। जब उनसे पूछा गया कि वह राहुल के संसदीय क्षेत्र बदलने के बारे में क्या कहना चाहते हैं तो जावड़ेकर लड़खड़ा गए। गौरतलब है कि राहुल इस लोकसभा में केरल के वायनाड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह 2004 से 2014 तक 10 साल उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

आपका पक्ष

दिल्ली में चले इलेक्ट्रिक बसें

दिल्ली में फिलहाल सार्वजनिक परिवहन सेवा में सीएनजी बसें चलती हैं। ये बसें दिल्ली परिवहन निगम की हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित एक मामला आया था तब मामले की सुनवाई के दौरान सीएनजी बसों से भी प्रदूषण से इनकार नहीं किया गया था। ऐसे में दिल्ली में चल रही डीटीसी बसों को भी इलेक्ट्रिक बसों में बदलने पर विचार करने की जरूरत है। दिल्ली में डीटीसी की 5,000 से अधिक बसें चलती हैं। अगर इन 5,000 बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदल दिया जाए तो दिल्ली की आबोहवा कुछ हद तक शुद्ध हो सकती है। सरकार ने वर्ष 2020 से बीएस-6 मानक वाले वाहनों को शुरू करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में बीएस-4 मानक वाले वाहन चल रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन लाने की तैयारी चल रही है। अगर सरकार इस योजना को सफल बनाना चाहती है तो पहले सरकारी स्तर पर इस कदम की शुरुआत होनी चाहिए। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में सार्वजनिक परिवहन सेवा में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करना चाहिए। इससे पर्यावरण के संरक्षण में कुछ हद तक सुधार संभव हो सकेगा। राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए सरकार को वित्तीय मदद करने की भी जरूरत है। दिल्ली में डीटीसी सभी सीएनजी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार को एक बार डीटीसी को वित्तीय पोषण करना चाहिए। इससे दिल्ली में 5,000 से अधिक सीएनजी बसों से होने वाला प्रदूषण खत्म हो जाएगा।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सोमवार को चेन्नई में ई-बस का शुभारंभ किया था *-पीटीआई*

कुपोषण में झारखंड, मध्य प्रदेश शीर्ष पर

झारखंड और मध्य प्रदेश बच्चों की कुशलता मापने वाले सूचकांक में खराब पोषण तथा शिशुओं के जीने की कम दर के कारण निचले पायदान पर हैं। इस सूचकांक का आकलन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी विकास, सकारात्मक संबंध और संरक्षण संबंधी विषयों के आधार पर किया जाता है। खबरों के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षण सुविधाओं के कारण केरल शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2000 में बिहार के अलग होने के बाद झारखंड में विकास की दर काफी धीमी रही है। अस्थिर राजनीतिक कारणों से भी यहां विकास कार्य प्रभावित हुआ है। खनिज भंडार की प्रचुरता के बावजूद झारखंड विकास नहीं कर पाया तथा यहां के शिशु कुपोषण के शिकार होते चले गए। राज्य सरकार को बच्चों के पोषण के लिए ग्रामीण स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। गांव के विकास से ही राज्य संपन्नता की ओर बढ़ सकता है। राज्य में अशिक्षा, बेरोजगारी के कारण लोगों को दो वक्त का समय नहीं मिल पाता है। अगर भोजन मिल भी जाता है तो उसमें पोषक तत्त्वों की कमी रह जाती है। राज्य के खनन क्षेत्र की स्थिति और भी चिंताजनक है। पश्चिम सिंहभूम में लौह अयस्क का भंडार है लेकिन यह जिला देश के सबसे पिछड़े तथा गरीब जिलों में आते हैं। जिले के किरीबुरू से लौह अयस्क निकलता है। लेकिन यहां के स्थानीय लोगों की माली हालत दयनीय है। अतः सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है।

देवेंद्र शर्मा, पश्चिम सिंहभूम

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।